

हुआ है इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है और यदि मान लो कोई ऐसी चीज होगी तो सरकार किसी कदम को उठाने में हिचकेगी नहीं। मैं इतना ही उनसे कहना चाहता हूँ।

श्री सभापति : वैरी गुड ।

SHRI S. MADHAVAN : So far as the recommendations on hank yarn are concerned, there cannot be any reconsideration about making available hank yarn for the handloom industry. Will the Government straightforwardly tell all the NTC mills to produce hank yarn to feed the handloom industry?

The other question is about the modernisation of sick textile industries. The Finance institution are refusing to assist the textile industry for modernising their machinery. There are a lot of sick mills coming up. Will the Government consider financing the sick units for modernising their machinery?

श्री शरद यादव : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो है आब्लीगेशन है, मैं मानता हूँ एन.टी.सी. उसको पूरा करने में अपनी वचनबद्धता को नहीं निभा रही है। अभी पिछले महीने की 15 तारीख में हम लोगों ने बैठक की थी। पूरे देश भर के जो स्पीनिंग मिल्स के मिल ऑनर्स थे उसको भी हमने बुलाया था। उसमें हमने हैक यार्न के पाँच परसेंट दाम भी कम करने का काम किया और यह मजबूती से कहा कि हैक यार्न के बारे में जो आब्लीगेशन है वह चाहें प्राइवेट ऑनर्स की मिल हों चाहे एन.टी.सी. हों, उन्हें इस आब्लीगेशन को पक्की तरह से पूरा करना पड़ेगा।

माडर्नाइजेशन का जो उन्होंने सवाल किया, सरकार इसमें सब तरह से लगी हुई है और आज दुनिया की जो रफ्तार है उसके साथ भी हमको चलना है। उस रफ्तार को बनाये रखने के लिये भी आज आधुनिकीकरण बहुत जरूरी चीज है और

हमारी सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है और माडर्नाइजेशन का जो पैकेज है उसको हम लोग आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं।

*122 [The questioner (Shri Chaturanan Mishra) was absent. For answer, vide Col....36....infra]

*123 [The questioner (Shri Suren Singh) was absent. For answer vide Col....37....infra]

*124 [The questioners (Chowdhary Hari Singh and Shri Krishna Kumar Birla) were absent. For answer vide Col....38....infra]

भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

*125. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में विकास तथा आधुनिकीकरण सम्बन्धी कोई कार्यक्रम हाथ में लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के फलस्वरूप इन दोनों संयंत्रों में इस्पात उत्पादन में हुए सुधार का भी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री : साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री विनोद गोस्वामी) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) दुर्गापुर इस्पातकारखाने के आधुनिकीकरण की परियोजना सितम्बर, 1987 में स्वीकृत का गयी थी, वह इस समय कार्यान्वयनाधीन है। 685 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा को शामिल करते हुए 2667.6 करोड़ रुपये

की अनुमानित लागत से इस कार्यक्रम को इस्पात के उत्पादन में तकनीकी आर्थिक सुधार जैसे कम उत्पादन लागत और ऊर्जा खपत तथा वर्धित जनशक्ति की उत्पादकता के अलावा कारखाने की अपरिष्कृत इस्पात की क्षमता को 16 लाख टन से बढ़ाकर 18.76 लाख टन वार्षिक करने में परिकल्पना की गई है। इस योजना को मार्च, 1993 तक पूरा कर लिये जाने के पश्चात् ही ये सुधार होंगे।

भिलाई इस्पात कारखाने के विनिष्ट क्षेत्रों का प्रायोगिक उन्नयन करने के लिये अनेक निजी योजनाएं आरम्भ की गयी हैं। परन्तु भिलाई इस्पात कारखाने को पूर्णतः आधुनिक बनाने के लिए पिछले दो वर्षों में न तो किसी विस्तृत कार्यक्रम को मंजूरी दी गई और न ही इस समय इस प्रकार का कोई कार्यक्रम सरकार के विचारार्थ है।

श्री शंकर दयाल सिंह : माननीय सभा-पति जी, सबसे पहले मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम लोग जो मूल प्रश्न हिन्दी में करते हैं उनका उत्तर अंग्रेजी में आता है और उसका अनुवाद हिन्दी में करके हम लोगों को मिलता है और मूल प्रश्न जो हिन्दी में करते हैं उसका मूल उत्तर अंग्रेजी में बनता है, उसके बाद अनुवाद हिन्दी में। उस अनुवाद से हम लोग कुछ नहीं समझ पाते। जैसा आज जो हमारे सामने सरकार की ओर से यह विवरण आया है हमारे प्रश्न के उत्तर में और उसमें है कि 685 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा को शामिल करते हुये आर्थिक सुधार जैसे कम उत्पादन लागत और ऊर्जा खपत तथा वर्धित जनशक्ति की उत्पादकता के अलावा कारखाने की अपरिष्कृत इस्पात की क्षमता। दूसरा है, विनिष्ट क्षेत्रों का प्रायोगिक उन्नयन।

सभापति जी, मैं स्वयं भी हिन्द का एक छोटा सा लेखक और जानकार हूँ, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति भी इस अनुवाद से अपने प्रश्न के उत्तर को नहीं समझ पा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा मीधे तीर से कि आपने अपने उत्तर में यह जो कहा है : 2667.6 करोड़ रुपये जिसमें 685 करोड़

की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। इतना खर्च करके आप दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इतना खर्च करने के बाद जो आप इसका विस्तार और आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं क्या उससे लोहे के मूल्य में कुछ कमी आयेगी जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके?

SHRI DINESH GOSWAMI : Sir, the hon. Member is a very distinguished writer in Hindi and may be because of that he used some words which are difficult for an ordinary Member to understand. Sir, the hon. Member has asked me this question whether after modernisation of Durgapur by which we hope to increase the capacity to 1.87 million tonnes from 1.60 million tonnes, there will be a fall in the prices of steel. Now, it is difficult to answer this question because the price of steel does not depend merely on increased production alone. Obviously with increased production the demand and supply gap will be reduced and the market will have its effect on the prices. But the price of steel is also dependent on the prices of the inputs, the exercise duty and all that. Therefore, within the time that the Durgapur project will be completed, and this project is likely to be completed after three years or so, other factors will have to be taken into account, for example, will the Finance Minister help me by not raising the excise duty? Will the Railway Minister help me by not raising the freight? These answers will only be evident during the budget that will come. I do not think, I am in a position to give any positive answers.

MR. CHAIRMAN : Do you think the cost of production will come down as things stand today?

SHRI DINESH GOSWAMI : About the cost of production, with increased supply, definitely in the market economy the pressure on price reduces.

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति जी, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया वह पूर्णतः सतोषजनक नहीं है क्योंकि खुद इनके स्टेटमेंट में यह लिखा हुआ है कि कम उत्पादन लागत और ऊर्जा खपत तथा बर्धित जनशक्ति की उत्पादकता के अलावा कारखाने की अपरिणत इस्पात की क्षमता के कारण कीमतों में कमी आयेगी, प्रोडक्शन कास्ट कम हो जायेगी। मैं खुद हिन्दी नहीं समझ पा रहा हूँ। मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि आपने इसमें यह कहा कि दाम कम नहीं होंगे यह कहना अभी कठिन है तो इसके साथ मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इतना पैसा खर्च करके आप माडर्नाइजेशन भी करते हैं और आप उसका विस्तार भी करते हैं तो क्या यह बात सही है कि पब्लिक सेक्टर में जो हमारे यहां इतने बड़े-बड़े संयंत्र कायम किये हुए हैं उनके बड़े अधिकारी प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के जो अधिकारी पब्लिक सेक्टर में आये हैं वे गवर्नमेंट के हित की रक्षा न करके उन्हीं प्राइवेट सेक्टर के हितों की रक्षा करते हैं और क्या वे इस तरह के संयंत्रों की खरीद करते हैं जो प्रायः खर्च करके प्रोडक्शन कम करते हैं और इसका लाभ सरकार को न मिलकर निजी क्षेत्रों की जो कंपनियां हैं उनको लाभ मिलता रहे ? मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप मूल्य वृद्धि करते हैं तो सरकार से अधिक प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिलता है ? जब-जब आपने स्टील की प्राइस बढ़ाई है तब-तब आप से अधिक टाटा को मुनाफा हुआ है या उन दूसरे औद्योगिक घरानों को लाभ हुआ है जो इसमें लगे हुए हैं ? मैं मंत्री महोदय से सीधे तौर पर जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात के लिए कोई इक्वायरी कमेटी बनेगी कि पिछले 10 साल के अन्दर जिन ऐसे कारखानों का विस्तार हुआ है या जहां ऐसे संयंत्र खोले गए हैं तो क्या उनकी उपयोगिता थी या नहीं थी और उनसे कौन सा लाभ हुआ ?

SHRI DINESH GOSWAMI :
Sir, so far as the answer to the first

part is concerned, obviously with increased production, prices are likely to come down unless extraneous factors contribute to the increase in prices. Apart from increased production, it has been our endeavour to bring down prices and I am happy to note that because of lesser cost consumption in the matter of power and other factors we have been able to bring down the cost of production. In fact, we are absorbing some of the wage increase without raising the prices. But I am compelled to raise the price because of the freight increase and also because of the increase of excise duty and sometimes of the prices of inputs. That is why I gave this answer. So far as the second part is concerned, even in SAIL, we have brought down the energy consumption from 11.30 giga calories to 8.3 giga calories which is contributing to the reduction of prices. But as I said, the price in a market economy is dependent on many factors and I have no control over some of the factors. So far as the second question is concerned, he is asking for a broad question whether the people who came from the private sector to the public sector really have their heart in the private sector or they do work even being in the public sector in the interest of the private sector. I do not think an affirmative answer will be appropriate. There are people who are in the private sector who come to the public sector and they are committed to the development of the public sector. Now, so far as the third question is concerned, whether such type of modernisation has some impact and what has been the impact of such modernisation. There are three modernisation proposals from the SAIL. Durgapur is currently on its way to modernisation. We are going ahead with the other two modernisation proposals. We are examining them. Therefore, at the present moment, it is not possible for me to answer a starred question.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिये सत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूँ कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के प्रकल्प की तैमसिक समीक्षा बैठकें क्या विदेशों में हुआ करती हैं। अगर यह सच है तो इन बैठकों का खर्चा कौन वहन करता है तथा इस तरह की बैठकें अभी तक किन-किन देशों में हो चुकी हैं ?

SHRI DINESH GOSWAMI : Sir, I require a specific notice for this. About the meetings she has asked. Therefore, I would require a specific notice.

MR. CHAIRMAN : She wants to know how many meetings are held outside.

SHRI DINESH GOSWAMI : On that, I would like to have a specific notice

MR. CHAIRMAN : You may communicate it to her.

श्री प्रमोद महाजन : इसके बाद बैठकें विदेशों में नहीं होंगी, यह तो कह सकते हैं।

श्री सभापति : ऐसे कैसे कह सकते हैं।

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY : Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the Government whether the Government has any plan to modify the re-rolling steel plant in Salem into a full-fledged steel plant in Salem as this is a long pending demand of Tamil Nadu.

SHRI DINESH GOSWAMI : Sir it is up to you. If I extend the scope of this question, there will be many other questions to all steel plants. But I can assure

MR. CHAIRMAN : No. no. But Salem has been there all the time.

SHRI DINESH GOSWAMI : I can assure you that Salem is very much under active consideration of the Government.

SHRI G. G. SWELL : Sir, I would like to know from the Minister whether a machine called 'Continuous Casting' machine is part of the modernisation package of the Durgapur Steel Plant and that the Durgapur Steel Plant authorities had paid a sum of Rs. 38 crores for this machine whereas about the same period, the Tata Steel purchased the same machine and paid only Rs. 4 crores. There is an unconscionable difference of Rs. 34 crores. Is the Minister in a position to confirm and deny that and if he cannot, can he make an enquiry and let the House know about it and let me also know about it ?

SHRI DINESH GOSWAMI : Sir, it is a fact that for Durgapur SAIL ordered a 'Continuous Casting' machine package from a firm of Switzerland named "Concast" at a total cost of Rs. 178 crores which had a foreign exchange component, I think of Rs. 38 crores. It came to our notice only sometime back that the TISCO ordered equipment of "Continuous Casting" which had cost them Rs. 30 crores. Now, we do not know whether both the sets of equipments are same or similar. When it came to our notice, I have asked for an examination of this matter. In fact, we have approached the Director General of Technical Developments, whose sanction is necessary for import of this. Therefore, this matter has come to my notice and I am examining it. I can only point out that these orders were placed long before we came to office.

MR. CHAIRMAN : You inform him about the same.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA : Sir, I would like to know because I think Durgapur Steel plant . . . and TISCO are the two sickmen of the steel industry.

I would like to know how much money has been spent on Durgapur Steel plant so far and what the total losses suffered by this steel plant so far are. The purpose of my wanting to know this information is to know whether we are throwing good money after bad money. Will this steel plant become economical compared to other steel plants?

SHRI DINESH GOSWAMI : Sir, so far as Burnpur is concerned, it is a fact that we are running the plant at a loss. In fact, because these Burnpur and Durgapur plants were getting sick, we thought that we must give a proper capital and technology injection through modernisation. It is our view that there is a definite gap between the demand and supply of steel in this industry and according to our estimation, at the terminal year of the Ninth Five-Year plan, there is going to be a deficit of two million tonnes of steel which will not only have its effect on prices but on the total economy. Therefore, the view of the Government, the view of the Steel Ministry, is that we should try to improve our production capacity by modernisation. In fact, even after the modernisation, we will not be able to fill the demand and supply gap. We are trying to persuade the planning Commission to go for two new steel mills. So far as Durgapur is concerned, the definitive cost estimate of Durgapur is...

MR. CHAIRMAN: He wants to know how much money you have spent and how much loss you have suffered.

SHRI DINESH GOSWAMI : I will give the exact figure of the money that has been spent.

MR. CHAIRMAN: He wants to know about Durgapur.

SHRI DINESH GOSWAMI : I am giving the figure. So far as Burnpur is concerned... *(Interruptions)*. He is asking about both.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: I wanted to know about Durgapur.

SHRI DINESH GOSWAMI : I will give the figures. So far as Burnpur is concerned, the modernisation proposal is under our examination. So far as Durgapur is concerned, I will give the figures to the hon. Member as to the exact amount we have spent so far.

*126 [*The questioner (Shri Santosh Bagrodia) was absent for answer vide col. ... infra*]

MR. CHAIRMAN: Question No. 127.

Introduction of Credit Card Scheme for Farmers

*127. **SHRI S. MADHAVAN :** Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have directed the commercial banks to introduce Credit Card Scheme for farmers; and

(b) if so, whether it is a fact that the crops financed under the Scheme will not be covered under crop insurance?

DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Public Sector Banks were advised by Government in April, 1988 to consider launching of Credit Card Scheme for farmers. Some public sector banks have introduced Agricultural Credit Cards in selected districts in a few States. These Cards are given to farmers who have a good track record to enable them to get agricultural credit, without difficulty to meet their cost of production inputs. The crops raised by